भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 661
06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमृत 2.0 के अंतर्गत परियोजनाएं

661. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है, अब तक पूरी की गई कुल परियोजनाओं की संख्या और वित्तीय व्यय क्या है तथा शेष परियोजनाओं के पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;

(ख) अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत प्रदान किए गए जल एवं सीवर कनेक्शनों की वर्तमान स्थिति क्या है, निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के मध्य कितना अंतर है तथा शेष लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं;

(ग) अमृत 2.0 में प्रौद्योगिकी उप-मिशन की भूमिका क्या है;

(घ) जल प्रबंधन के क्षेत्र में नवीनतम वैश्विक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) इससे मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता मिलेगी?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 को 01 अक्टूबर 2021 को परियोजनाओं के लिए 66,750 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) के साथ लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अमृत 2.0 दिशानिर्देशों के व्यापक ढांचे के भीतर परियोजनाओं का चयन, प्राथमिकता, कार्यान्वयन और निगरानी करने का अधिकार है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) की

सिफारिश के अनुसार अमृत 2.0 के तहत राज्य जल कार्य योजनाओं (एसडब्ल्यूएपी) को अनुमोदित करता है। परियोजना कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों की है। अमृत 2.0 के तहत शुरू की गई प्रमुख परियोजनाएं लंबी अवधि वाली जल और सीवरेज क्षेत्र में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं।

अमृत 2.0 के अंतर्गत, 1,89,188 करोड़ रुपये (संचालन और रखरखाव लागत सहित) की कुल 8,887 परियोजनाओं को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। अमृत 2.0 पोर्टल पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार (27.01.2025 तक), 5,383 परियोजनाओं के लिए 92,284.01 रुपये के मूल्य के अनुबंध दिए गए हैं। कुल 27,183.78 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य वास्तविक रूप से पूरे हो चुके हैं और 20,834.92 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

(ख): अमृत मिशन के अंतर्गत राज्यों के साथ समन्वय करके 139 लाख के लक्ष्य की तुलना में 189 लाख नल कनेक्शन (नए/सेवित) प्रदान किए गए हैं तथा 145 लाख के लक्ष्य की तुलना में 149 लाख सीवर कनेक्शन (नए/सर्विस्ड) (फेकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन-एफएसएसएम के माध्यम से कवर किए गए घरों सहित) प्रदान किए गए हैं।

(ग) से (ङ): प्रौद्योगिकी उप-मिशन, स्टार्ट-अप विचारों और निजी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और उन्हें पायलट परियोजनाओं में शामिल करने के लिए अमृत 2.0 का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह जल और प्रयुक्त जल शोधन, वितरण और जलाशयों के पुनरुद्धार के क्षेत्र में नवाचारी, सिद्ध और संभावित पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों की पहचान की सुविधा प्रदान करता है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की "स्टार्ट-अप इंडिया" पहल द्वारा दी गई परिभाषा को पूरा करने वाले स्टार्ट-अप भाग लेने के पात्र हैं। इस उप-मिशन के तहत, अब तक 120 स्टार्ट-अप को ऑनबोर्ड किया गया है और 82 अमृत शहरों के साथ मैप किया गया है। अब तक, 105 स्टार्ट-अप ने अपने पायलट शुरू कर दिए हैं।

*****